

### प्रेस विज्ञप्ति

#### लोकसभा चुनाव 2009 उम्मीदवारों द्वारा दायर चुनावी खर्च के आधार पर खर्च विश्लेषण

- 19% उम्मीदवारों ने अपना चुनावी खर्चा दायर नहीं किया।
- 2 सांसदों और कई उम्मीदवारों ने जिनमे मुख्य दलों के उम्मीदवार भी सम्मिलित हैं अभी तक अपना चुनावी खर्चा दायर नहीं किया है।
- Average election expense of candidates of all parties is between 50-55% (or less) of the prescribed limit of 25 Lakhs.
- Former CEC J.M Lyngdoh, Super cop Julio Rebeiro, General (retd) Shankar Roychowdhury and Former DGP I C Dwevedi ने चुनावी खर्चों में कड़े नियमों के पालन का अह्वान किया है।

दिल्ली , दिसम्बर 9 ,2009 :- Association for Democratic Reforms (ADR) and नेशनल इलेक्शन वाच ( NEW ) ने चुनाव आयोग से विभिन्न प्रतियोगियों के चुनावी खर्च के सारांश को एकत्रित किया है जिसके आधार पर निम्नलिखित विश्लेषण किया गया है। हालाँकि NEW ने सभी उम्मीदवारों का चुनावी खर्च का ब्यौरा माँगा था किन्तु आयोग केवल 463 निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण ही उपलब्ध करवा पाया.

शेष बचे हुए निर्वाचन क्षेत्रों के लिए DEOs को अभी अपनी रिपोर्ट्स आयोग को भेजनी हैं ! NEW ने चुनाव आयोग को डेटा को जल्द उपलब्ध करवाने का अह्वान किया है.

जैसे ही सारा डेटा उपलब्ध होगा NEW इसे सभी को उपलब्ध करवाएगा

#### विश्लेषण का सारांश :-

1. NEW 543 निर्वाचन क्षेत्रों के 8028 उम्मीदवारों में से केवल 463 निर्वाचन क्षेत्रों के 6753 उम्मीदवारों के चुनावी खर्च का सारांश प्राप्त कर पाया है ! इनमें से 1266 उम्मीदवारों ने अपने चुनावी खर्च को दाखिल नहीं किया है , दुसरे शब्दों में 19% उम्मीदवारों ने अपने खर्च दर्ज नहीं किये हैं !
2. वो उम्मीदवार जिन्होंने अपने चुनावी खर्च दाखिल नहीं किये हैं उनमें से कई उम्मीदार ऐसे हैं जो मुख्य पार्टियों के उम्मीदवार हैं ! BSP के 421 में से 64 उम्मीदवार , BJP के 361 में से 13 उम्मीदार और INC के 374 उम्मीदवारों में से 7 उम्मीदवारों ने अपने खर्च दाखिल नहीं किये हैं.
3. विजेताओं में 463 निर्वाचन क्षेत्रों में से 2 विजेता जो वर्तमान सांसद हैं, ने अपना चुनावी खर्च दाखिल नहीं किया है. ये 2 सांसद हैं- कबीर सुमन जो AITC पार्टी से हैं और जाधवपुर पश्चिम बंगाल से सांसद हैं , दुसरे हैं चौधरी मोहन जतुआ AITC पार्टी से मथुरापुर पश्चिम बंगाल से सांसद हैं.
4. केवल 4 उम्मीदवारों ने निर्धारित खर्च से अधिक खर्च किया है। इनमें पश्चिम बंगाल के मुरादाबाद से AUDF के जफ़ुला मुल्ला (रु. 49 लाख ), बिहार के पश्चिम चम्पारण से LJP पार्टी के प्रकाश झा (रु 45.27 लाख ), उत्तर प्रदेश के फतेपुर सिकरी से रघुराज साकिया(रु. 41 लाख ) SP पार्टी से और आगरा से रामजी लाल सुमन (रु. 31 लाख )

SP से है.

5. पश्चिम बंगाल में अधिकतम निर्धारित खर्च 25 लाख है जबकि मुर्शिदाबाद से AUDF पार्टी के जफरुल्ला मुल्ला ने अधिकतम खर्च 49 लाख घोषित किया है.

6. केवल चार उम्मीदवारों का खर्च चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा से अधिक था इसके अलावा, केवल 30 उम्मीदवारों का चुनाव के दौरान खर्च की सीमा के 90% के बीच खर्चा था , (अधिक से अधिक खर्च ₹.22.5 लाख) और सीमा (₹. 25 लाख ). इन सभी उम्मीदवारों की सूची की रिपोर्ट के साथ संलग्न है.

7. पार्टी वार विश्लेषण के दौरान पाया गया की मुख्य पार्टियों के उम्मीदवारों द्वारा किया गया खर्च अधिकतम निर्धारित खर्च सीमा के करीब था. जिसमें पार्टी वार औसत खर्चा सबसे अधिक INC द्वारा ₹.13 .7 लाख , BJP द्वारा ₹. 12.5 लाख , SP द्वारा ₹.8.9 लाख और BSP द्वारा ₹.6.2 खर्च किया है.

8. राज्य वार विश्लेषण में किसी भी राज्य में औसत खर्च निर्धारित सीमा के 50 % भी नहीं है , अधिकतम खर्च लक्षद्वीप (₹. 476787 ) और मणिपुर (₹. 1055823 ) में 48 % और मेघालय (₹. 790013 ) में 36 % था ।

9. 10 लाख से कम सम्पति वाले उम्मीदवारों का औसत चुनावी खर्च ₹. 1.34 लाख .10 लाख से 50 लाख की सम्पति वाले उम्मीदवारों का औसत चुनावी खर्च 4 .10 लाख था । 50 लाख से 5 करोड़ सम्पति वालों की औसत चुनावी खर्च बढ़कर 9 .37 लाख था. 5 करोड़ से अधिक सम्पति वालों का औसत चुनावी खर्च 11 .8 लाख ₹.था

10 . उत्तर प्रदेश के 2 उम्मीदवार द्वारा घोषित चुनावी खर्च शून्य है दोनों निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिनमें संजय सलीमपुर से और सुनील कुमार उन्नाव से है.

11. औसत अधिकतम खर्च वाले निर्वाचन क्षेत्रों में आसाम का कोकारा झार (₹. 1617642 ) स्थान प्रथम था , उसके बाद कर्णाटक के बेल्लारी (₹. 1476363 ) , मेघालय से तुरा (₹. 1350700 ) था । न्यूनतम खर्च वाले निर्वाचन क्षेत्रों में तमिलनाडु से टेनी (₹. 29371 ) का था , उसके बाद तमिलनाडु से चैन्नई नोर्थ (₹. 86727 ) और बिहार से आरा (₹. 100431 ) था ।

12. विजेताओं का विश्लेषण करने पर पाया गया की पार्टी वार विजेताओं का औसत चुनावी खर्च निर्धारित सीमा (25 lakhs) से बहुत कम था । मुख्य पार्टियों का औसत खर्च प्रति उम्मीदवार INC का ₹. 14 .3 लाख, BJP- 15 .04 लाख , AITC - ₹. 15 .8 , BSP - ₹. 14 .32 लाख , JD (U) - ₹. 15 .57 लाख , SP - ₹. 16 .31 लाख था

13. देश के 79 निर्वाचन क्षेत्रों चुनाव खर्च का ब्यौरा उपलब्ध नहीं हो सका ।

14. सभी सांसदों का चुनावी खर्च की सूची संलग्न है.

**Commenting on the results of these analyses, Former CEC Mr J. M Lyngdoh of National Election Watch said, "Going by the average election expenses of the candidates during lok sabha elections it seems our politicians are very poor people. These expenses should be computed not by the government but by external competent authorities. We should change over to a better system otherwise it is meaningless to have count of such expenses. "**

**General (retd) Shankar Roychowdhury of National Election Watch said,** “Given present trends of lavish political campaigning in most of the states it is extremely surprising and difficult to believe that most of the candidates haven’t even spent 50% of the prescribed election expense limit. I have doubts regarding the accuracy of the expense statements declared by candidates. In fact, it seems that the expenses declared by candidates are a farce and seem to be making mockery of the entire system”.

**Former Super cop Julio Rebeiro of National Election Watch said,** “While voters saw naked display of money power in the Lok Sabha elections, it is surprising that most candidates have shown that they did not even spend money up to the election expense limit of 25 Lakhs. Political parties also must be held accountable for such candidates who by not declaring their expenses have made a mockery of Indian elections and democracy. In addition to a great need for lot more scrutiny of these expenses, this also points to an urgent need for making political parties accountable”.

**Former DGP, I C Dwevedi of National Election Watch said,** “Electioneering has been getting frightfully expensive and 'money-power' has now become a major factor. If a candidate were to honestly show the entire expenditure incurred it would amount to many times the permissible limit. That the average declared expenditure is less than 50% of the permissible limit amply demonstrates totally 'inadequate and ineffective' compliance with the rules.”

#### Contact

<p>Anil Bairwal, National Coordinator National Election Watch, and Association for Democratic Reforms</p> <p>011 6590 1524, +91 9999310100 <a href="mailto:adr@adrindia.org">adr@adrindia.org</a>, <a href="mailto:anil@adrindia.org">anil@adrindia.org</a></p>	<p>Prof Trilochan Sastry Dean, IIM Bangalore Founder Member, National Election Watch, Association for Democratic Reforms</p> <p>+919448353285, <a href="mailto:trilochans@IIMB.ERNET.IN">trilochans@IIMB.ERNET.IN</a></p>	<p>Prof Jagdeep Chhokar Former Director IIM Ahmedabad, Founder Member National Election Watch, Association for Democratic Reforms</p> <p>+919999620944 <a href="mailto:jchhokar@gmail.com">jchhokar@gmail.com</a></p>
---	---	---

#### About NEW

The *National Election Watch (NEW)* is a nationwide campaign comprising of more than 1200 NGO and other citizen led organizations working on electoral reforms, improving democracy and governance in India. The National Election Watch is active in almost all states of India and has done election watch for all states and Lok Sabha elections since ADR, along with a couple other organizations, won the PIL in Supreme Court in 2002 making disclosure of educational, financial and criminal background of electoral candidates mandatory.

#### About ADR

Association for Democratic Reforms (ADR) is a Non-Political, Non-Partisan and a Non-Governmental Organization whose PIL filed in Dec 1999 culminated in a Supreme Court order on Mar 13, 2003 requiring disclosure of criminal, financial and educational background of all contesting candidates. Since then ADR has done Election Watches in almost all State Assembly and Lok Sabha

elections. It continues to work towards strengthening democracy and governance in India by focusing on fair and transparent electoral and political processes.  
You can learn more about ADR at: <http://www.adrindia.org>